

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 388/ 2-6, गोरखपुर, दिनांक अगस्त 16 / 2022

Office Phon e/Fax No. 0551-2333558 E-Mail ID- ccfgorakhpurmandal@gmail .com

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय— जनपद— देवरिया के अन्तर्गत भारत पेटोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया— कसया मार्ग (एस०एच०— 79) 18 से 19 (चैनेज— 18.620) के मध्य दायी पटरी पर गाटा सं०— 166 ग्राम— सिरसिया पट्टी हुसैन, तहसील व जिला— देवरिया में प्रस्तावित पेटोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित एरिया 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 05 अदद वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आपका पत्रांक 2295/ 11— सी— एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/51457/ 2020 दिनांक 03-02-2022 एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग देवरिया का पत्रांक 255/ 2-6, दिनांक 30-07-2022

महोदय,

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग देवरिया ने अपने पत्रांक 255/ 2-6, दिनांक 30-07-2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रस्ताव की तीन प्रतियों संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित हैं।

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या— /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग देवरिया को उनके पत्रांक 255/ 2-6, दिनांक 30-07-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

जी

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

सहमत है।

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

प्रस्ताव स्वीकृत करने की संहति
की जा रही है।

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक- 25-01-2022

स्थान- गोरखपुर

हस्ताक्षर

नाम
मुख्य वन संरक्षक
लेफ्टिनेंट कमांडर, गोरखपुर
सरकारी मोहर